चमड़ा और जूता निर्यात हो सकता है दोगुना : गोयल

मुक्त व्यापार समझौते से 1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, हजारों नए रोजगार सृजित होंगे

नई दिल्ली, 29 जुलाई. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, ब्रिटेन को भारत का चमड़ा और जूते का निर्यात तीन साल में लगभग दोगुना होकर 1 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है. यह आंकड़ा 2024 के 49.4 करोड़ डॉलर से काफी अधिक है.

गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्यातकों के साथ एक बैठक में बताया कि यह समझौता सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, तकनीकी मानकों को संरेखित करेगा और कोल्हापुरी जूते तथा मोजरी जैसे भारतीय भौगोलिक संकेत उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. इससे भारतीय

उत्पादों को ब्रिटेन के 8.7 अरब डॉलर के विशाल चमड़ा और जूते के बाजार में बेहतर दृश्यता प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते से देश भर के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों को लाभ मिलेगा. मांग में अनुमानित वृद्धि से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों , कारीगरों, महिला उद्यमियों और युवा-नेतृत्व वाले उद्यमों में हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारतीय उत्पादों पर यूके के आयात शुल्क को समाप्त करता है. यह शुल्क चमड़े के सामान के लिए 2त्न से 8त्न, चमड़े के जूतों के लिए 4.5त्न और गैर-चमड़े के जूतों के लिए 11.9त्न के बीच था. यह भारतीय निर्यातकों के लिए बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले समान अवसर प्रदान करता है, जिन्हें यूके के बाजार में बेहतर पहुँच प्राप्त है. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1,700 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला

> यह समझौता वाणिज्य विभाग द्वारा भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा सृजित अवसरों पर चर्चा करने के लिए कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के हितधारकों के साथ संवाद के लिए आयोजित किया गया था. इस समझौते से भारत के वस्त्र उद्योग को भी फायदा मिलेगा और तिरुपुर, जयपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, भदोही और मुरादाबाद जैसे सभी प्रमुख कपड़ा क्लस्टर को लाभ होगा.

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रमऔर फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित केंद्रित उत्पाद योजना जैसी सरकारी पहल क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मेगा क्लस्टर और डिजाइन स्टूडियो के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड प्रचार में सहायक हैं.

जीएसटी संग्रह में 10 .7% की बढ़ोतरी

पहली तिमाही में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1,80,774 करोड़

छोटे कारोबारियों को पंजीकरण में छूट की सीमा 40 लाख रुपये तक

नई दिल्ली, 29 जुलाई. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद को बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औसत मासिक शुद्ध जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1,80,774 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में औसत मासिक शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,63,319 करोड़ रुपए था.

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने स्मॉल बिजनेस सेक्टर के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं.अगर छोटे और मध्यम उद्यम राज्य के भीतर कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल हैं साथ ही उनका कुल कारोबार एक वित्त वर्ष में 40 लाख रुपए (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 20 लाख रुपए) से अधिक नहीं है तो उन्हें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है.

इसी तरह, अगर किसी वित्त वर्ष में राज्य के भीतर या अंतर-राज्यीय कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति में शामिल व्यक्तियों का कुल कारोबार 20 लाख रुपए (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए) से अधिक नहीं है तो उन्हें जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है.

एथर एनर्जी और सरकार में ईवी साझेदारी

डीपीआईआईटी और एथर एनर्जी ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के तहत बिल्ड इन भारत की साझेदारी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (वार्ता) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में स्वच्छ परिवहन और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के विकास में तेज़ी लाने के लिए भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर किए हैं.

मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवाचार-केंद्रित 50 से अधिक स्टार्टअप्स के गठबंधन स्टार्टअप पॉलिसी फ़ोरम (एसपीएफ) के नेतृत्व में 'बिल्ड इन भारत' पहल के अंतर्गत यह सहयोग किया जा रहा है.

यह समझौता ज्ञापन डीपीआईआईटी और एथर एनर्जी के बीच व्यापक साझेदारी की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. यह साझेदारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्टअप्स के रणनीतिक मार्गदर्शन, उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं की मूल्य श्रृंखला से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज जैसे संयुक्त नवाचार कार्यक्रमों, प्रतिभा और कौशल विकास पहलों की मिलकर मेजबानी, और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के साथ-साथ जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त करने पर केंद्रित होगी.

> डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव सिंह और एथर एनर्जी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तरुण मेहता की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए . इस पहल से भारत में दीर्घकालिक परिवहन व्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा मिलने और विनिर्माण की ओर बढ़ रहे स्टार्टअप्स को अधिक सक्षम करने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार होने की उम्मीद है . सिंह ने हस्ताक्षर समारोह में कहा, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र बदलाव के महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहा है .

सेंसेक्स 447 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊँचाई पर

446 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स

140 अंक की बढ़त पर पहुंचा निफ्टी

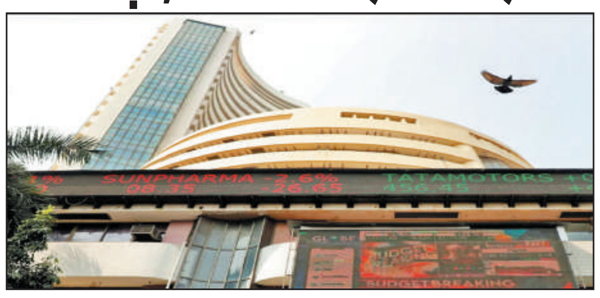

मुंबई, 29 जुलाई (वार्ता) घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को चौतरफा लिवाली के दम पर बीएसई का सेंसेक्स 446.93 अंक यानी 0.55 प्रतिशत की मजबूती के साथ 81,337.95 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 140.20 अंक (0.57 प्रतिशत) चढ़कर 24,821.10 अंक पर पहुँच गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के साथ एलएंडटी और भारती एयरटेल ने भी बाजार की बढ़त में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

एशियाई बाजारों से मिले मिश्रित रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार सुबह गिरावट में रहे. सेंसेक्स करीब 271 अंक टूटकर 80,620.25 अंक पर खुला और 80,575.45 अंक तक उतर गया. यूरोप में बाजार खुलने और वहाँ तेजी रहने से दोपहर बाद घरेलू बाजारों में भी लिवाली शुरू हो गयी और सेंसेक्स बीच कारोबार में 81,429.88 अंक को छूने में कामयाब रहा. इसी प्रकार, निफ्टी-50 भी 30 अंक की गिरावट में 23,663 अंक पर खुला. इसका दिन का निचला स्तर 23,620.90 अंक रहा जबकि ऊपर यह 23,936 अंक तक गया.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 19 के शेयर हरे निशान में बंद हुये. रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.21 प्रतिशत और एलएंडटी का 2.13 प्रतिशत की मजबूती में रहा.

एलएंडटी को पश्चिम एशिया में मिला अल्ट्रा-मेगा ऑर्डर

मुंबई, 29 जुलाई (वार्ता) निर्माण क्षेत्र की देश की अग्रणी कंपनी एलएंडटी की अपतटीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में काम करने वाली इकाई को एक पश्चिम एशियाई क्लाइंट से अल्ट्रा-मेगा ऑर्डर मिला है. कंपनी ने जो परिभाषा साझा की है, उसके अनुसार 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर को अल्ट्रा-मेगा ऑर्डर कहते हैं. एलएंडटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि एलएंडटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर इस ऑर्डर के तहत उसे इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और अपतटीय ढाँचे स्थापित करने की जिम्मेदारी मिली है. साथ ही मौजूदा संयंत्रों को अपग्रेड करने का काम भी वह करेगी.

प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात बढ़ाने की जरूरत : पासवान

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (वार्ता). केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि देश के खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की हिस्सेदारी फिलहाल 23 प्रतिशत है जिसे और बढ़ाने की जरूरत है.

पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (आईआईए) द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना- उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य से विषय पर आयोजित एक क्षेत्रीय सेमिनार में कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है. उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर किसानों और छोटे उद्यमियों के साथ अपनी भागीदारी को और मजबूत करें. उन्होंने कहा कि देश तब तक वास्तव में सक्षम नहीं बन सकता जब तक हमारे किसान सशक्त न हों. इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक परिवर्तनकारी कदम है.

तेल और गैस अन्वेषण में नई तेजी

अंडमान गहरे पानी क्षेत्र पर विशेष ध्यान-हरदीप पुरी

नीतिगत सुधारों से मिली गति, नो-गो क्षेत्रों को खोला गया

नई दिल्ली29 जुलाई (वार्ता) भारत में तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, खासकर अपतटीय और सीमांत क्षेत्रों में. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि अंडमान-निकोबार बेसिन राष्ट्रीय और वैश्विक हित का नया केंद्र बन गया है.

इस गति का श्रेय 2014 से शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों, रणनीतिक भूकंपीय सर्वेक्षणों और नए अन्वेषण दृष्टिकोण को जाता है. मंत्री के अनुसार, 2022 में लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर के पहले प्रतिबंधित %नो-गो% अपतटीय क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोलना एक महत्वपूर्ण मोड़ था. इस कदम ने गहरे पानी के ब्लॉकों में गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से भूवैज्ञानिक रूप से आशाजनक अंडमान-निकोबार अपतटीय बेसिन में, जिसकी भूवैज्ञानिक निरंतरता म्यांमार और इंडोनेशिया से है.

2015 से, भारत के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र ने 172 हाइड्रोकार्बन खोजों की सूचना दी है, जिनमें 62 अपतटीय ब्लॉकों से हैं. राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने क्षेत्र में स्ट्रैटिग्राफिक कुओं की ड्रिलिंग शुरू कर दी है, जिसमें 5,000 मीटर तक की गहराई को लक्षित किया गया है.

जियो ने लॉन्च किया एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर

जियो-पीसी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप, टीवी को बनाए स्मार्ट कंप्यूटर

नई दिल्ली, 29 जुलाई, कंप्यूटर की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी, रिलायंस जियो ने नया जियो-पीसी लॉन्च किया है. यह एक क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफ़ॉर्म है. जो आपके घर या दफ्तर में मौजूद टीवी स्क्रीन को पलभर में हाईएंड पर्सनल कंप्यूटरमें बदल सकता है.

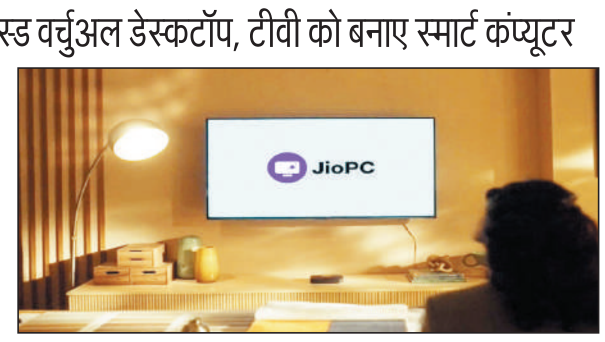

जिन ग्राहकों के पास जियोफाइबर या जियो एयरफाइबर के कनेक्शन हैं, उन्हें जियो-पीसी का इस्तेमाल करने के लिए मंथली प्लान लेना होगा. नए उपयोगकर्ता इस सेवा का एक महीने के लिए मुफ़्त उपयोग कर सकेंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग में यह देश का पहला 'पे-एज़-यू-गो मॉडल' है, यानी जितना इस्तेमाल करो उतना पेमेंट करो. कंपनी ने इस सेवा के लिए कोई लॉक-इन पीरियड नहीं रखा है. ग्राहक को रखरखाव का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता. किसी महंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अपग्रेड की आवश्यकता भी नहीं होगी. बस प्लग इन करें, साइन अप करें और कंप्यूटिंग शुरू करें. कंपनी का दावा है कि क्लाउड बेस्ड जियो-पीसी काफी ताकतवर है. इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी शानदार है और यह रोजमर्रा के कामकाज के साथ गेमिंग और ग्राफिक रेंडरिंग जैसे हाईएंड काम भी आसानी से संभाल सकता है. जियो-पीसी जैसी क्षमता वाला कंप्यूटरबाजार में 50 हजार रु से अधिक का मिलता है.

नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल ने हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाया

जबलपुर। नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल और एएमपीआईएन एनर्जी ट्रांजिशन ने अपनी साझेदारी को और मजबूत करते हुए 125.65 मेगावॉट सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक नया पावर-व्हीलिंग समझौता किया है, जो इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) से जुड़े प्लांट्स के जरिए दी जाएगी। इस नई साझेदारी के साथ दोनों कंपनियों के बीच कुल रिन्यूएबल एनर्जी सहयोग 200 मेगावॉट के पार पहुँच चुका है। नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल के सीईओ आशीष अरोड़ा ने कहा, %सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक वादा नहीं है - यह हमारी जिम्मेदारी है और नेतृत्व का अवसर भी। एएमपीआईएन के साथ 200 मेगावॉट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी से अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देकर हम इंडस्ट्री के लिए नए मानक स्थापित कर रहे हैं।

समाचार विशेष

योगी आदित्यनाथ ने रचा इतिहास

बने यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 8 साल 127 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 8 वर्ष, 4 माह और 10 दिन का निर्बाध और निर्णायक कार्यकाल पूरा कर लिया है. यह रिकॉर्ड केवल वर्षों और महीनों की गिनती नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक रूपांतरण की गाथा है, जो योगी सरकार के दौर में लिखी गई.

योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल ऐसे समय में जारी है जब प्रदेश में एक समय अराजकता, अपराध और राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला हुआ करता था. लेकिन बीते आठ वर्षों में शासन-प्रशासन में नवाचार, पारदर्शिता और सख्ती के चलते उन्होंने 'नए उत्तर प्रदेश' की बुनियाद रखी. आज प्रदेश की पहचान कानून व्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे के नए मानकों से हो रही है. मुख्यमंत्री योगी अब राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व और जनता के विश्वास का चेहरा बन चुके हैं.

बुनियादी ढांचे और निवेश में क्रांतिकारी बदलाव - योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. गोरखपुर एम्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नोएडा फिल्म सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने यूपी को विकास की नई धुरी बना दिया है. इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि राज्य की छवि भी बदली है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की सुलभता और प्रभाव को सुनिश्चित किया. प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, जैसी योजनाओं ने न सिर्फ लोगों को राहत दी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बदलाव लाया.

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल केवल एक सरकार की कहानी नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति के बदलाव और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मिसाल है . जहां उत्तर प्रदेश एक समय अपराध, जातिवाद और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, वहीं अब यह बिजनेस, निवेश और बदलाव का चेहरा बनता जा रहा है . योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा केवल किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिपक्वता, प्रशासनिक स्थिरता और विकास की परिभाषा में क्रांतिकारी बदलाव का परिचायक है . अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस रिकॉर्ड को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं और क्या वह वाकई में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने के अपने संकल्प को पूरी तरह साकार कर पाएंगे .

आरजेडी के खिलाफ उतरेंगे लालू के लाल

पटना. बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. तेज प्रताप ने साफ कर दिया है कि इस बार वह महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे.

काफी समय से राजनीति में सक्रिय तेज प्रताप ने कहा, 'हमने 'टीम तेज प्रताप यादव' बनाई है. यह कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक खुला मंच है, जहाँ सभी को जुड़ने और काम करने का मौका मिलेगा.' तेज प्रताप ने आगे कहा कि लोग लगातार 'टीम तेज प्रताप' से जुड़ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं.' हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल कोई पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है.

महुआ सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला- तेज प्रताप ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. लालू के लाल ने यह भी बताया कि उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना और युवाओं को एक मंच प्रदान करना है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, तेज प्रताप का यह कदम न केवल राजद के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बल्कि महुआ सीट पर एक दिलचस्प मुकाबले की ज़मीन भी तैयार कर रहा है. गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने पहले भी कहा था कि अगर राजद उन्हें टिकट नहीं देती है, तो वे महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. तेज प्रताप ने साफ़ कहा था, 'हमने महुआ के लिए काम किया है, इसलिए हम महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे.

विशेष | करना पड़ेगा मंत्रिमंडल में बदलाव?

विवादित मंत्रियों ने बढ़ाई सरकार की चिंता

मुंबई. कथित विवादास्पद वीडियो और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों ने राज्य की महागठबंधन सरकार के कुछ मंत्रियों को मुश्किल में डाल दिया है और अब मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा चल रही है. हालांकि यह तय नहीं है कि संबंधित मंत्रियों को वास्तव में बर्खास्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन इससे मंत्री पद के इच्छुक अन्य लोगों की उम्मीदें ज़रूर बढ़ गई हैं. समझा जाता है कि सत्तारूढ़ दल के इच्छुक विधायकों ने भी अपने-अपने तरीके से मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है.

राज्य में महायुति सरकार को बने अभी छह-सात महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग तीन-चार मंत्री विवादों में घिर गए हैं. विधानसभा सत्र चल ही रहा था कि शिवसेना

के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का उनके ही बेडरूम का एक वीडियो सामने आया. इस वीडियो में उनके साथ पैसों से भरा बैग नज़र आने का दावा किया गया. संजय शिरसाट ने खुद बताया कि उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है.

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम- इसके बाद, सत्र समाप्त होने के बाद, उभय पक्ष ने गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर अपनी मां के एक बार पर छापा मारने और वहां बारबालाओं का अश्लील नृत्य करने का आरोप लगाया.

> **स्थानीय निकाय चुनाव**
>
> विपक्ष के इन आरोपों से यह कयास लगाया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में सरकार को झटका लग सकता है . इसलिए, यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस इन अक्षम, विवादास्पद मंत्रियों में से कुछ को घर का रास्ता दिखा सकते हैं . यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घटनाक्रम स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ही होने की संभावना है . समझा जाता है कि विधायकों ने अपना नाम चुनावी मैदान में उतारने के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है .

विपक्ष भी लड़ेगा उप राष्ट्रपति का चुनाव

नई दिल्ली . उप राष्ट्रपति के नाम पर आम सहमति बनने के आसार कम हैं . हालांकि विपक्षी पार्टियों ने अभी खुल कर कुछ नहीं कहा है लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है . कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल कर रणनीति तय करेंगी . गौरतलब है कि भारत में उप राष्ट्रपति पद के लिए आमतौर पर चुनाव होता है . जिसकी सरकार रहती है वह आम सहमति बनाने का प्रयास करने की बात करता है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती है . पिछली बार यानी 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मारग्रेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया था . हालांकि उनको इलेक्टोरल कॉलेज का महज 25 .63 फीसदी ही वोट मिल पाया था और 74 फीसदी से ज्यादा वोट लेकर जगदीप धनखड़ जीते थे . उससे पहले 2017 में विपक्ष ने भाजपा के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के खिलाफ महात्मा गांधी के पोते गोपालकृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया था . उनको 32 .11 फीसदी वोट मिले थे .

कार्यालय नगरपालिका परिषद वारासिवनी , जिला - बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/1647,1876/लो .नि .वि ./न .पा .प ./2025, // **निविदा आमंत्रण सूचना** // वारासिवनी, दिनांक 14/07/2025, 28/07/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं .	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
01	02	03	04	05	06
1.	क्र . 2025_UAD_ 440548_1 दिनांक : 29/07/2025	Construction of Badminton Court and Playing Equipment at infront of Indoor Stadium at Ward No. 05 Waraseoni	समयावधि : 4 माह लागत : 9,17,454/-	नि .प्र .मूल्य : 2,000/- EMD : 9,175/-	18/08/2025
2.	क्र . 2025_UAD_ 442655_4 दिनांक : 29/07/2025	Supply and Fixing of RCC and PVC Pipe	समयावधि : (वार्षिक) लागत : 3,00,000/-	नि .प्र .मूल्य : 2,000/- EMD : 3,000/-	18/08/2025

नोट : - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, वारासिवनी